

## कसिन आंदोलन 2.0 और MSP

### प्रलिमिस के लायि:

न्यूनतम समरथन मूलय, कसिन आंदोलन 2.0 और MSP, भूमि अधिग्रहण अधनियम, 2013, विद्युत (संशोधन) वधियक 2020, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की रपोर्ट।

### मेन्स के लायि:

कसिन आंदोलन 2.0 और MSP, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संग्रहण, विकास, विकास और रोज़गार से संबंधित मुद्दे।

### सरोत: इंडियन एक्सप्रेस

### चर्चा में क्यों?

न्यूनतम समरथन मूलय (Minimum Support Price - MSP) के लायि कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब, हरयाणा और उत्तर प्रदेश के कसिन 'दलिली चला' वरिध प्रदर्शन में दलिली की ओर मार्च कर रहे हैं।

- वर्ष 2020 में कसिनों ने, दलिली की सीमाओं पर, सरकार द्वारा पारति तीन कृषि कानूनों का वरिध कथि, जसिके कारण वर्ष 2021 में उन्हें नरिस्त कर दिया गया।
- ये कानून थे- कृषि उपज वाणिय एवं व्यापार (संवरदधन एवं सुवधि) वधियक, 2020, मूलय आशवासन पर कसिन (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा वधियक, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) वधियक, 2020

### कसिनों की मुख्य मांगें क्या हैं?

- कसिनों के 12 सूत्रीय एजेंडे में मुख्य मांग सभी फसलों के लायि न्यूनतम समरथन मूलय (MSP) की गारंटी के लायि एक कानून और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (मनकोम्बु संबांशविन स्वामीनाथन) आयोग की रपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का नरिधारण करना है।
  - स्वामीनाथन आयोग की रपोर्ट में कहा गया है कसिरकार को **MSP** को उत्पादन की भारति औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिये। इसे C2+ 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है।
  - इसमें कसिनों को 50% रटिरन देने के लायि पूँजी की अनुमानति लागत और भूमिपर करिया (जसि 'सी2' कहा जाता है) शामलि है।
  - भूमि, शरम और पूँजी जैसे संसाधनों के उपयोग की अवसर लागत को ध्यान में रखने के लायिअध्यारोपति लागत (**imputed cost**) का उपयोग कथि जाता है।
  - पूँजी की अध्यारोपति लागत उस ब्याज या रटिरन को दरशाती है जो अर्जति कथि जा सकता था यदि कृषि में नविश की गई पूँजी को कहीं और नविश कथि जाता है।
- अन्य मांगें:
  - कसिनों और मज़दूरों की पूरण क्रज्ज माफी;
  - भूमि अधिग्रहण अधनियम, 2013 का कार्यान्वयन, जसिमें अधिग्रहण से पहले कसिनों से लखिति सहमति और कलेक्टर दर से चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान है।
    - संग्राहक दर (**collector rate**) वह न्यूनतम मूलय है जसि पर कसी संपत्तिको खरीदते या बेचते समय पंजीकृत कथि जा सकता है। वे संपत्तयों के कम मूल्यांकन और कर चोरी को रोकने के लायि एक संदर्भ बद्दि के रूप में कार्य करते हैं।
  - अकट्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा;
  - भारत को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization - WTO) से बाहर हो जाना चाहिये और सभी मुक्त व्यापार समझौतों (free trade agreements - FTAs) पर रोक लगा देनी चाहिये।
  - कसिनों और खेतिहर मज़दूरों के लायि पेशन।
  - वर्ष 2020 में दलिली वरिध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले कसिनों के लायि मुआवजा, जसिमें परवार के एक सदस्य के लायि नौकरी भी शामलि है।

### सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

- नवंबर 2021 में भारत सरकार ने तीन कृषिकानूनों को रद्द करने के बाद MSP पर एक समतिबिनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य MSP पर चर्चा करना, [जीरो बजट नेचुरल फारमगि](#) को बढ़ावा देना और फसल पैटर्न पर नरिण्य लेना था। इस समतिका गठन जुलाई 2022 में किया गया था और इसने अब तक कोई रपिएट नहीं दी है।
- कैबिनेट मंत्रालय और कसिन अधिकारी के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठक के दौरान सरकार नेकृषि, ग्रामीण तथा पशुपालन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक नई समतिबिनाने की पेशकश की।
- यह समतिकसिनों की सभी फसलों के लिये MSP की मांग का समाधान करेगी। सरकार ने वादा किया कि यह नई समतिनियमति रूप से बैठक करेगी और नियमित समय सीमा के भीतर काम करेगी।

## MSP के कानून में चुनौतियाँ हैं?

- जबरन खरीद (Forced Procurement):
  - सरकार को MSP पर सभी उपज खरीदने का आदेश देने से अत्यधिक उत्पादन हो सकता है, जिससे संसाधनों की बरबादी और भंडारण की समस्या हो सकती है।
  - यह फसल पैटर्न को भी विकृत (distort) कर सकता है क्योंकि कसिन अन्य फसलों की तुलना में MSP वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे जैवविविधता और मटिटी के संवास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
  - यदि सरकार को उपज खरीदनी पड़ती है क्योंकि MSP की पेशकश करने वाला कोई खरीदार नहीं है, तो उसके पासड़ी मात्रा में भंडारण करने और बेचने के लिये संसाधन नहीं हैं।
- कसिनों का आपसी भेदभाव (Discrimination Among Farmers):
  - ऐसा कानून समर्थति फसलों उगाने वाले कसिनों और अन्य फसलों उगाने वाले कसिनों के बीच असमानता पैदा कर सकता है।
  - बगि समर्थन वाली फसलों उगाने वाले कसिनों को बाजार पहुँच और सरकारी समर्थन के मामले में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
- व्यापारियों का दबाव (Pressure From Traders):
  - फसल कटाई के दौरान, कृषिउपज की कीमतें आमतौर पर सबसे कम होती हैं, जिससे नजीबी व्यापारियों को फायदा होता है जो इस समय खरीदारी करते हैं। इस बजह से, नजीबी व्यापारी MSP के कसी भी कानूनी आश्वासन का वरिध करते हैं।
- वित्तीय बोझ (financial burden):
  - सभी फसलों को MSP पर खरीदने की बाध्यता के कारण बकाया भुगतान और राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- सामाजिक नहितार्थ (Societal Implications):
  - विकृत फसल पैटर्न और अत्यधिक खरीद के व्यापक सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, जो खाद्य सुरक्षा, प्रयावरणीय स्थरिता तथा समग्र आरथक स्थरिता को प्रभावित कर सकते हैं।

## MSP को कानूनी रूप देने के बजाय कसिनों की आय की रक्षा के लिये क्या पहल की जा सकती है?

- विशेषज्ञ केवल MSP पर नियम रहने के बजाय कसिनों को सीधे पैसा देने का सुझाव देते हैं। इस तरह, कसिनों को स्थिर आय मिलती है, चाहे बाजार कैसा भी हो।
  - इसका संबंध कुछ फसलों के लिये कीमतों की गारंटी देने के बजाय कसिनों के पास प्रयाप्त पैसा नहीं होने की बड़ी समस्या को ठीक करने से है।
- प्रत्यक्ष आय सहायता को लागू करने में विभिन्न रणनीतियाँ शामिल हो सकती हैं, जैसे कि:
  - प्रत्यक्ष नकद हस्तातरण: कसिनों को उनकी आय बढ़ाने और वित्तीय तनाव कम करने के लिये सीधे नकद भुगतान प्रदान करना।
    - सरकार पूरे मूल्य समर्थन पैकेज और उत्तरक सब्सिडी को शामिल करके तथा राजस्व-तटस्थ तरीके से कसिनों को बहुत अधिक पीएम-कसिन भुगतान में [PM- कसिन योजना](#) का विस्तार करने के बारे में सोच सकती है।
    - यह योजना वरतमान में कसिनों को प्रत्यक्ष 6000 रुपए सीधे नकद भुगतान प्रदान करती है।
  - बीमा योजनाएँ:
    - ऐसी बीमा योजनाएँ शुरू करना जो फसल की वफिलता, मूल्य अस्थरिता या प्रतकूल मौसमीय स्थिति जैसे कारकों के कारण कसिनों की आय के नुकसान की भरपाई करती हैं।
    - कृषि आदानों (inputs), उपकरणों, परोदयोगिकी अपनाने और उच्च मूल्य वाली फसलों या वैकल्पिक आजीविका में विधिकरण का समर्थन करने के लिये सब्सिडी या अनुदान की पेशकश करना।
  - मूल्य-अंतरण भुगतान विकल्प: सरकार MSP और कसिनों द्वारा बेची जाने वाली दर के बीच मूल्य अंतर का भुगतान करने पर भी विचार कर सकती है।
    - हरयाणा और मध्य प्रदेश ने [भावांतर भरपाई योजना](#) (मूल्य-अंतरण मुआवजा योजना) नामक योजना के तहत इस विकल्प को लागू किया है।
    - मध्यप्रदेश की 'भावांतर भुगतान योजना' के तहत कसिनों को भुगतान औसत बाजार मूल्य और फसलों के MSP के बीच के अंतर को कवर करता है। यदि कसिनों को खुले बाजार में MSP से नीचे अपनी उपज बेचनी पड़ी, तो उन्हें मुआवजा दिया गया।

## WTO और FTA से संबंधित कसिनों की चतिएँ क्या हैं?

- बाजार तक पहुँच:
  - कसिनों को चति है कीFTA और WTO नयिमों से सस्ते कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं तथा स्थानीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है।
  - कसिन इन समझौतों को छोटे और मध्यम आकार के कसिनों के बजाय बहुराष्ट्रीय नयिमों तथा बड़े पैमाने के कृषि व्यवसायों के पक्ष में मानते हैं।
- आयातति वस्तुएँ:
  - इन समझौतों से अन्य देशों से सबसेडी वाले कृषि उत्पादों की आमद होती है, जिससे घरेलू बाजार में बाढ़ आ सकती है और स्थानीय रूप से उत्पादित फसलों की कीमतें कम हो सकती हैं।
  - इससे भारतीय कसिनों के लिये प्रतिस्पर्धा करना और अपनी आजीवकियां बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
- कृषि प्रदूषणों पर प्रभाव:
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते कृषि प्रदूषणों पर ऐसे नयिम या मानक भी लागू करते हैं जिन्हें भारतीय कसिन अपनी पारंपरिक खेती प्रदूषणों के साथ बोझलि या असंगत पाते हैं।
  - इसमें कीटनाशकों के उपयोग, आनुवंशिक रूप से संशोधन जीव या प्रयोगरण मानकों से संबंधित आवश्यकताएँ शामिल हो सकती हैं।
- संप्रभुता और स्वायत्तता:
  - कुछ कसिन WTO से हटने तथा मुक्त व्यापार समझौतों पर अंकुश लगाने को भारत की कृषि नीतियों पर संपूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण हासिल करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं।
  - उनका तरक है कीऐसे समझौते लघु पैमाने के कसिनों के हतियों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों के कार्यान्वयन और नागरिकों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चयिता करने में सरकार की क्षमता को सीमित करते हैं।

## MSP और कसिनों की मांग की वर्तमान स्थितिक्र्या है?

- मौजूदा MSP बनाम कृषियों की मांगें:
  - रबी मार्केटगी सीज़न 2024-25 के लिये सरकार द्वारा नियंत्रित गेहूँ का MSP 2,275 रुपए प्रति किलो नियंत्रित किया गया है जो कसिनों द्वारा मांगी गई लागत यानी C2 पलस 50% से अधिक है।
  - हालाँकि MSP A2+FL फॉर्मूले पर आधारित है जिसमें केवल कसिनों द्वारा भुगतान की गई लागत शामिल है जिसके परणिमस्वरूप C2 पलस 50% की तुलना में MSP कम है।
- CACP की अनुशंसा और कार्यप्रणाली:
  - कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) A2+FL फॉर्मूले के आधार पर MSP नियंत्रित करने की अनुशंसा करता है जिसमें केवल भुगतान की गई लागत तथा पारवारिक शरम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है।
    - यह C2 फॉर्मूले से भनिन है जिसमें कसिन के स्वामित्व वाली भूमि के करिये और स्थरि पूँजी पर ब्याज जैसे अतिरिक्त कारक शामिल हैं।
- उत्पादन लागत पर रटिरन:
  - पंजाब में गेहूँ का उत्पादन लागत (C2) 1,503 रुपए प्रति किलो है जबकि नियन्त्रित समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपए प्रति किलो है।
    - इसका अरथ यह है कि किसिनों को उत्पादन लागत से 772 रुपए प्रति किलो अधिक मिलता है जो उत्पादन लागत पर 51.36% का रटिरन दर्शाता है।
    - इसी प्रकार पंजाब में धान की उत्पादन लागत पर रटिरन 49% का था और A2+FL पर यह 152% था।

## विश्व भर में कसिन वरिएध प्रदर्शन कर रहे हैं?

- दक्षणि अमेरिका:
  - कसिन नियंत्रित के लिये प्रतिकूल वनियिय दर, अधरिपति उच्च कर, आरथकि मंदी और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारकों के कारण वरिएध कर रहे हैं जिनसे फसलें प्रभावित होती हैं तथा कृषि उत्पादन कम होता है।
    - ब्राज़ील में कृषक वर्ग आनुवंशिक रूप से संशोधन मक्का के परणिमस्वरूप होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा के विद्युद्ध वरिएध प्रदर्शन कर रहे हैं।
    - वेनेजुएला में कसिन सहायकी युक्त डीज़ल की मांग कर रहे हैं।
    - कोलंबियाई धान उत्पादक अपनी फसल के लिये कीमतों में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं।
- यूरोप:
  - कसिन फसल की कम कीमतों, बढ़ती लागत, अल्प लागत वाले आयात और युरोपीय संघ द्वारा अधरिपति सख्त प्रयोगरण नयिमों का वरिएध कर रहे हैं।
    - फ्रांस में अल्प लागत वाले आयात, अप्रयोगत सहायकी और उच्च उत्पादन लागत के विद्युद्ध वरिएध प्रदर्शन किये जा रहे हैं।
- उत्तर और मध्य अमेरिका:
  - मैक्सिकोन कसिन मक्कों और गेहूँ की फसल के लिये दिये जाने वाले अनुचित कीमतों का वरिएध कर रहे हैं जबकि कोस्टा रिका के कसिन कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने के लिये अधिक सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं।
  - मैक्सिको के चहुआहुआ प्रांत में संयुक्त राज्य अमेरिका को सीमित जल आपूर्ति नियंत्रित करने की योजना पर वरिएध प्रदर्शन हुआ।
- एशिया:
  - भारतीय कसिन फसल की गारंटीकृत कीमतों, आय दोगुनी करने और ऋण माफी की मांग को लेकर वरिएध प्रदर्शन कर रहे हैं।
  - नेपाल में आयातति भारतीय सब्ज़र्यों की अनुचित कीमतों के कारण वरिएध प्रदर्शन किया जा रहा है।
  - मलेशियाई और नेपाली कसिन क्रमशः चावल तथा गन्ने की कम कीमतों का वरिएध कर रहे हैं।

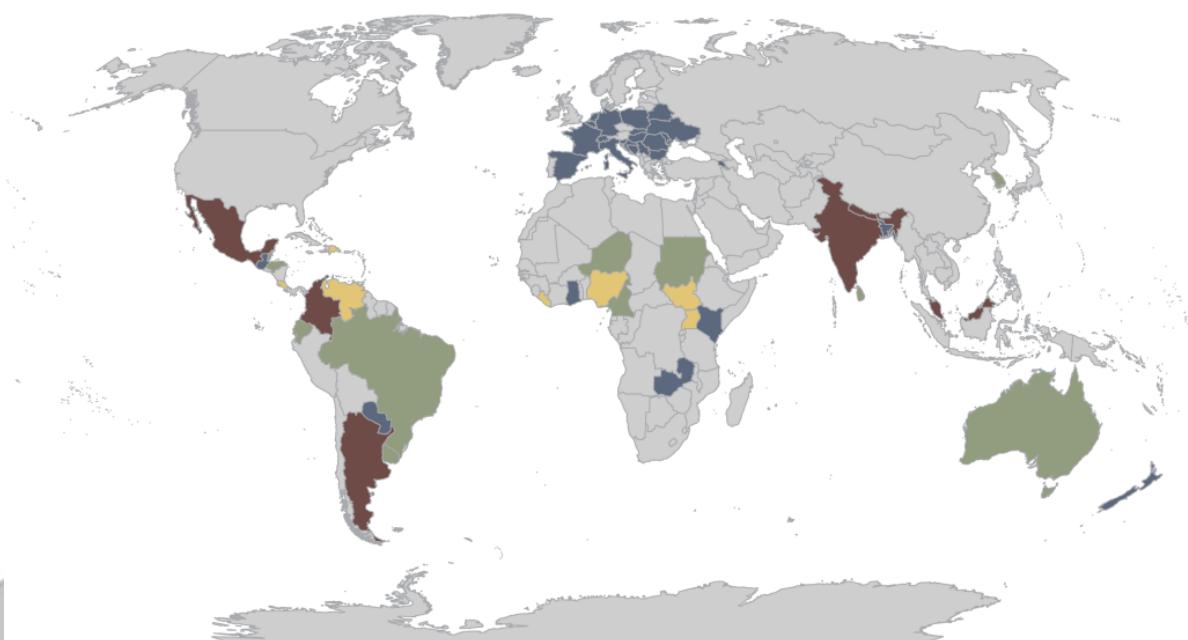
- **ओशनिया:**

- नयूजीलैंड के कसिन खाद्य उत्पादकों को प्रभावित करने वाले सरकारी नियमों का वरिष्ठ करते हैं जबकि ऑस्ट्रेलियाई कसिन अपनी कृषि भूमि से गुज़रने वाली हाई-वोल्टेज विद्युत लाइनों का वरिष्ठ कर रहे हैं।

## FARM PROTESTS GLOBALLY

Since 2023, at least 65 countries have reported protests organised by agricultural workers with reasons ranging from minimum support price like in India, to unfair governmental policies — like in Europe — to outright displacement or eviction of farmers as seen in Benin or Sudan in Africa

### Protesting over...



*Source: Media reports*

**Down To Earth**

## न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

- **परचिय:**

- MSP वह गारंटीकृत राशि है जो कसिनों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है।
- MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सफिराशियों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूरति, बाजार मूल्य उद्घान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
  - CACP कृषिएवं कसिन कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसका गठन जनवरी 1965 में किया गया।
- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आरथकि मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) MSP के स्तर पर अंतमि नियम (अनुमोदन) लेती है।
- MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विधिकरण को प्रोत्साहित करना है।

- **MSP के तहत फसलें:**

- CACP, 22 अधिकृत फसलें (Mandated Crops) के लिये MSP और गन्ने के लिये उचित तथा लाभकारी मूल्य (FRP) की सफिराशि करता है।
- अधिकृत फसलों में खरीफ सीज़न की 14 फसलें, 6 खरी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।

- **उत्पादन लागत के तीन प्रकार:**

- CACP प्रत्येक फसल के लिये राज्य और अखलि भारतीय औसत स्तर पर तीन प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है।
  - ‘A2’: इसके तहत कसिन द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, इधन, सचिवाई आदिपर कथि गए प्रत्यक्ष व्यय को शामलि कथि जाता है।
  - ‘A2+FL’: इसके तहत ‘A2’ के साथ-साथ अवैतनकि पारविवारकि श्रम का एक अधरीपति मूल्य शामलि कथि जाता है।
  - ‘C2’: यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत ‘A2+FL’ में कसिन की स्वामतिव वाली भूमि और स्थरि संपत्ति के करिए तथा ब्याज़ को भी शामलि कथि जाता है।
- नयूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सफिरशि करते समय CACP द्वारा ‘A2+FL’ और ‘C2’ दोनों लागतों पर वचिर कथि जाता है।
  - CACP द्वारा ‘A2+FL’ लागत की ही गणना प्रतफिल के लिये की जाती है।
  - जबकि ‘C2’ लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बैचमारक लागत के रूप में कथि जाता है, यह देखने के लिये किक्या उनके द्वारा अनुशंसति MSP कम-से-कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं।
- **MSP की आवश्यकता:**
  - वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में लगातार दो सूखे (Droughts) की घटनाओं के कारण कसिनों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा।
  - **विमुद्रीकरण (Demonetisation)** एवं **‘वस्तु एवं सेवा कर’** ने ग्रामीण अरथव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर-कृषकिधेतर के साथ-साथ कृषि कधेतर को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कथि है।
  - वर्ष 2016-17 के बाद अरथव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोवडि महामारी के कारण अधिकांश कसिनों के लिये परदृश्य वकिट बना हुआ है।
  - डीज़ल, बजिली एवं उर्वरकों के लिये उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया है।
  - यह सुनिश्चिति करता है कि कसिनों को उनकी फसलों का उच्चति मूल्य मलि, जिससे कृषि सिंकट एवं नरिधनता को कम करने में मदद मलिती है। यह उन राज्यों में वशीष रूप से प्रमुख है जहाँ कृषि आजीवकि का एक प्रमुख स्रोत है।





# न्यूनतम समर्थन मूल्य

## Minimum Support Price (MSP)

**वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर**

- सिफारिश:
- 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
- 22 अधिदिष्ट फसलें :
- (14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)
- 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- 5 दालें- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
- 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
- कच्चा कपास
- कच्चा जूट
- नारियल/गरी (कोपरा)

**MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदिष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है**

- MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:
- ❖ फसल की खेती में आने वाली लागत
- ❖ फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
- ❖ बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
- ❖ अंतर-फसल मूल्य समता
- ❖ उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
- ❖ पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
- ❖ कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
- ❖ MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
- ❖ MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है

## भारत में MSP व्यवस्था से संबद्ध समस्याएँ:

- सीमतिता:
  - 23 फसलों के लिये MSP की आधिकारिक घोषणा के विपरीत केवल दो- चावल और गेहूँ की खरीद की जाती है क्योंकि इनहीं दोनों खाद्यान्नों का वितरण [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम \(NFSA\)](#) के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्वपूर्ण ही है।
  - शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि गैर-लक्षित फसलें उगाने वाले अधिकांश कसियाँ को MSP से लाभ नहीं मिलता है।
- अप्रभावी कार्यान्वयन:
  - वर्ष 2015 की शांता कुमार समतिकी रपोर्ट के अनुसार कसियाँ को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त हुआ।
  - जसिया अर्थ यह है कि देश के 94% कसियाँ MSP के लाभ से बचति रहे। इसका मुख्य कारण कसियाँ के लिये अप्राप्त खरीद तंत्र और बाजार पहुँच है।
- प्रवण फसल का प्रभुत्व:
  - चावल और गेहूँ के लिये MSP पर ध्यान केंद्रित करने से इन दो प्रमुख खाद्य पदार्थों के पक्ष में फसल पैटर्न में बदलाव आया है। इन फसलों पर अत्यधिक बल देने से पारस्परिक, आर्थिक और पोषण संबंधी प्रभाव पड़ सकते हैं।
  - यह बाजार की मांगों के अनुरूप नहीं हो सकता है, जिससे कसियाँ के लिये आय की संभावना सीमित हो सकती है।
- बचौलियों पर नियन्त्रण:
  - MSP-आधारित खरीद परिणामी में प्रायः बचौलिये, कमीशन एजेंट और [कृषिउपज बाजार समितियों \(APMC\)](#) के अधिकारी जैसे बचौलिये शामिल होते हैं।
  - वशीष रूप से छोटे कसियाँ के लिये इन चैनलों तक पहुँच चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिससे अक्षमताएँ उत्पन्न होंगी और उनके लिये लाभ कम हो जाएगा।
- सरकार पर बोझः
  - सरकार MSP समर्थन फसलों के बफर स्टॉक की खरीद और रखरखाव में एक बहुत वित्तीय बोझ उठाती है। इससे उन संसाधनों का विचलन हो जाता है जिन्हें अन्य कृषिया ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये आवंटित किया जा सकता है।

## आगे की राह

- फसल विधिकरण को प्रोत्साहिति करने और चावल व गेहूँ के प्रभुत्व को कम करने के लिये सरकार धीरे-धीरे MSP समर्थन हेतु पातर फसलों की सूची का विस्तार कर सकती है। इससे कसियाँ को अधिक विकल्प मिलेंगे और बाजार की मांग के अनुरूप फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- MSP मुद्दे का समाधान करने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कसियाँ के हतों और व्यापक आर्थिक नियतिरथ कोई शामिल किया जाना चाहिये।
- MSP प्रक्रिया पर ध्यान प्रदान करने और MSP नियंत्रण करने के लिये एक नियंत्रक तथा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने से कसियाँ द्वारा उठाई गई कुछ चित्तियों को दूर करने में मदद मिल सकती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नियन्त्रित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों एवं तिलिहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्राप्त भारत के कसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (यू.टी.) में असीमित होता है।
2. अनाजों एवं दालों का MSP कसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर नियंत्रित किया जाता है, जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1  
(b) केवल 2  
(c) 1 और 2 दोनों  
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

प्रश्न. नियन्त्रित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

1. भारत सरकार काले तलि नाइजर (गुइज़ोटिया एबसिनिका) के बीजों के लिये न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है।
2. काले तलि की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है।
3. भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तलि के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिये प्रयोग में लाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

### प्रश्न:

प्रश्न. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का नमिन आय फंदे से कसि प्रकार बचाव करेगा? (2018)

प्रश्न. सहायकियाँ सस्यन प्रतिरूप, सस्य विधिता और कृषकों की आरथिक स्थितिकसि प्रकार प्रभावति करती है? लघु और सीमांत कृषकों के लिये फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है? (2017)

प्रश्न. धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिये कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? (2020)

प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायकी का प्रतिस्थापन भारत में सहायकियों के परादीश्य का कसि प्रकार प्रविरतन कर सकता है? चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. वशिव व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) एक महत्वपूरण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए नियन्य देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ का क्या अधिदिश (मैंडेट) है और उसके नियन्य कसि प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पछिले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/16-02-2024/print>